तिब्बत देश

दलाई लामा का नया बयान और चीनी खिसियाहट

चीन और दूसरे देशों के रिश्तों में ऐसे मौके अकसर आते हैं जब मौके की नज़ाकत आंख से दिखने वाली घटना से नहीं बल्कि उस पर चीनी नेताओं की प्रतिक्रिया से समझ आती है। इस बात को पिछले दिनों दलाई के उस बयान पर चीनी प्रतिक्रिया से अच्छी तरह समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने अपने शासकीय और राजनीतिक अधिकार तिब्बत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सौंपने की घोषणा की है। उन्हों यह भी कहा है कि वह नए दलाई लामा के चुनाव की परंपरा को आधुनिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलना चाहते हैं ताकि उनके बाद वाले दलाई लामा पुनर्जन्म के बजाए योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाएं।

लेकिन दलाई लामा की इस घोषणा पर चीनी प्रतिक्रिया उसने स्पष्ट कर दिया है कि तिब्बत और दलाई लामा को लेकर चीनी नेता कुछ खास मंसूबे पाले बैठे हैं। बीजिंग ने दलाई लामा की इस घोषणा का जवाब देने के लिए अपने एक वरिष्ठ तिब्बती कारिंदे पेमा छोलिंग को चुना जो चीनी शासकों का विशेष कृपापात्र है और इन दिनों तिब्बत का गवर्नर है। बीजिंग में विदेशी पत्रकारों को दिए अपने बयान में पेमा ने दलाई लामा की घोषणा को तिब्बती संस्कृति का अपमान बताते हुए कहा कि ''हमें तिब्बत की ऐतिहासिक परंपराओं और तिब्बती बौद्धधर्म के धार्मिक अनुष्ठानों का सम्मान करना चाहिए। तिब्बती बौद्धधर्म का इतिहास हजार साल से भी पुराना है और दलाई लामा तथा पंचेन लामा के पुनरावतार की परंपरा कई सौ साल से चलती आ रही है। .... मेरे हिसाब से किसी व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि पुनर्जन्म के आधार पर (धार्मिक नेताओं के) नए अवतार ढूंढने की परंपरा बंद की जाए या नहीं।''

पेमा के माध्यम से चीन सरकार के इस बयान ने पिछले कई साल से चली आ रही इस आशंका को सच साबित कर दिया है कि बीजिंग के शासक वर्तमान दलाई लामा के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी मर्जी के किसी बच्चे को उनकी जगह 'नए अवतार' के रूप में बिठाकर तिब्बत की समस्या से छुट्टी पा लें। तिब्बत–चीन रिश्तों पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञ यह देखकर हैरान हैं कि तिब्बत पर कब्जे के बाद दशकों तक तिब्बती मठों, मंदिरों, तिब्बती भाषा और तिब्बती सामाजिक परंपराओं को घोषित नीति के तहत तहस–नहस करने वाली चीन सरकार को अब अचानक ही तिब्बत की 'ऐतिहासिक परंपराओं' और तिब्बती बौद्धधर्म के 'धार्मिक अनुष्ठानों' के 'सम्मान' की चिंता सताने लगी है।

ऐसा नहीं कि दलाई लामा चीनी चालों से बेखबर हैं। निर्वासन में आने के बाद से ही वह तिब्बती शासन व्यवस्था को पुरानी धार्मिक बंदिशों से मुक्त करके एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं जो दलाई लामा के बजाए खुद अपने बल पर तिब्बती संघर्ष को चला सके और जिसका जीवनकाल उनके अपने व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा लंबा हो। इस दिशा में एक नामित संसद से शुरू करके पिछले 50 साल में उन्होंने तिब्बत के लिए संविधान और गुप्त मतदान पर आधारित ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी कर दी है जिसमें निर्वाचित संसद को दलाई लामा तक को हटाने का अधिकार हासिल है। पंद्रह बार निर्वाचित संसद के अलावा पिछले सप्ताह तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे वोट से किया गया। दलाई लामा ने अपने राजनीतिक अधिकार इसी संसद और प्रधानमंत्री को सौंपने की घोषणा की है।

चीन सरकार के मौजूदा धार्मिक प्रेम को समझने के लिए तिब्बत में पिछले दो तीन दशक के घटनाक्रम को समझना होगा। तिब्बत में अपने कारिंदा प्रशासकों से 'तिब्बत में सब कुछ ठीक ठाक है' सुनते रहने के आदी बीजिंग शासकों को 1989 में तब बहुत सदमा लगा था जब तिब्बती जनता ने चीन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। इस विद्रोह की कमान ऐसे तिब्बती युवा संभाले हुए थे जो चीनी शासन में पैदा हुए थे और चीनी शिक्षा और राजनीतिक घुट्टी पीकर बड़े हुए थे। उनके नारों और मांगों पर दलाई लामा, तिब्बती आज़ादी और धार्मिक आजादी की गहरी छाप थी जिन्हें उनकी पीढ़ी ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं देखा था।

इस आंदोलन का गहन विश्लेषण करने के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 'तीसरे वर्क फोरम' ने 1991 में तय किया कि चीन विरोध को कुचलने के लिए तिब्बती धर्म का विनाश करने के बजाए उसके इस्तेमाल के तरीके भी खोजे जाने चाहिएं। उसके बाद लोगों को मंदिर जाने की छूट दी गई तथा टूरिस्ट उपयोग वाले मठों मंदिरों को फिर से सजाने संवारने का अभियान शुरू किया गया। मठों में सीमित संख्या में लामाओं को सीमित छूट देने के साथ उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की 'देशभक्ति' कक्षाएं भी अनिवार्य कर दी गईं। कई मठों को अपने अवतारी लामा ढूंढने की भी छूट दी गई।

चीन के प्रयासों से जून 1992 में खोजे गए कर्मापा को निर्वासन से दलाई लामा की मान्यता दिलाने के बाद खुद बीजिंग सरकार ने भी नए अवतार को मान्यता दी। इस सफलता से उत्साहित चीनी शासकों ने पंचेन लामा के अवतार की खोज के लिए भी 1995 में पार्टी की देखरेख में लामाओं की कमेटी बनाई। लेकिन कुछ लामाओं ने बीजिंग से पहले दलाई लामा को खबर भेजकर 6 वर्षीय नए अवतार गेधुन छयोकि न्यीमा को उनकी मान्यता दिला दी। गुस्से में बिफरे चीनी प्रशासन ने गेधुन और उसके माता पिता को हिरासत में लेकर अपनी मर्जी के एक अन्य बालक गियांसेन नोरबू को असली 'पंचेन लामा' घोषित कर दिया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और सैंकड़ों मानवाधिकार संगठनों की मांग के बावजूद न तो पंचेन लामा को आज तक रिहा किया गया है और न उनकी सुरक्षा का कोई प्रमाण पेश किया गया।

यह अलग बात है कि सारे सरकारी प्रचार के बावजूद गियांचेन नोरबू को तिब्बती जनता ने आज तक स्वीकार नहीं किया। अपनी कई हजार किमी की तिब्बत यात्राओं में मुझे आज तक कोई ऐसा घर, दुकान, रेस्टोरेंट या रिक्शा नहीं दिखा जिसमें उसका फोटो लगाया गया हो। उधर 2000 की नववर्ष रात्रि में कर्मापा भी चीनी पहरेदारों को चकमा देकर भारत भाग आए।

लेकिन चीन सरकार ने छोटे मोटे नए लामा अवतारों को खोजने और उन्हें खुश रखने का अपना अभियान जारी रखा हुआ है। पिछले कई साल से वह अपने दर्जनों बौद्ध 'विद्वानों' को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सेमिनारों में भेजती है। वह खुद दो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कर चुकी है जिनमें अपने सरकारी 'पंचेन लामा' को पूरे तामझाम के साथ पेश किया जाता है पर दलाई लामा और अन्य तिब्बती विद्वानों को उनमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता।

इस पूरे धार्मिक अभियान का एक लक्ष्य दुनिया को यह दिखाना है कि चीन सरकार बौद्ध धर्म से बहुत प्यार करती है। लेकिन शायद असली इरादा उस दिन के लिए तैयारी करना है जब वर्तमान दलाई लामा स्वर्ग सिधारें और चीन की धरती पर बीजिंग सरकार के चुने हुए किसी बच्चे को 'असली' दलाई लामा के रूप में पेश करके अपना नया पिट्ठू खड़ा कर दिया जाए। उस चीनी पिट्ठू को तिब्बत की जनता से कितनी मान्यता मिलेगी यह तो पंचेन लामा के उदाहरण ने पहले ही सिद्ध कर दिया है। लेकिन दलाई लामा ने अपने राजनीति अधिकार चुने प्रतिनिधियों को सौंपकर और नए दलाई लामा के चुनाव की व्यवस्था बदलने की बात कहकर तिब्बत के औपनिवेशिक आकाओं के इरादों पर पानी फेर दिया है। इसलिए अगर चीन के शासक दलाई लामा को धर्म विरोधी बताकर खुद को तिब्बत की 'ऐतिहासिक परंपराओं' और 'तिब्बती धार्मिक अनुष्ठानों' का सही वारिस बताने के लिए गुस्सा दिखा रहे हैं तो खंभा नोचने की उनकी खिसियाहट को समझा जा सकता है।

– विजय क्रान्ति

तिब्बत में तीन खनिज बेस विकसित करेगा चीन

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार 24 फरवरी को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में जिया ने कहा, "हमें दलाई लामा गुट के खिलाफ लड़ाई तेज कर देनी चाहिए, स्थिरता बनाए रखने का हर काम ज्यादा सतर्कता से करना चाहिए और तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में भी ठोस काम करना चाहिए।"

(पीटीआई, 7 फरवरी)

चीन अगले पांच सालों में तिब्बत में तीन बड़े खनिज आधार विकसित करने की योजना बना रहा है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि तिब्बत के उक्त इलाकों में 102 प्रकार के खनिज भंडार हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 100 अरब डॉलर हो सकती है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ की खबरों के अनुसार तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) केंद्रीय इलाकों जैसे ल्हासा शहर और शन्नान प्रशासनिक क्षेत्र में तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमियम और सोना का अन्वेषण कार्य तेज करेगा ताकि गैर लौह धातुओं और क्रोम्स के लिए एक बड़ा खनिज बेस तैयार किया जा सके। खबर के अनुसार टीएआर के पूर्व में स्थित चामदो प्रशासनिक क्षेत्र में एक गैर लौह धातु बेस तैयार किया जाएगा। यह ऐसा इलाका है जिसमें अगले साल से शुरू होने वाले पंचवर्षीय योजना में 1.5 करोड़ टन तांबा, शीशा और जस्ते का भंडार मिलेगा। इसके अलावा तिब्बत के उत्तर–पश्चिम में स्थित एक खारे झील वाले इलाके को लवणीय धातुओं और लीथियम का एक बड़ा बेस बनाने की उम्मीद है। कई तरह के खनिज भंडारों में से तिब्बत के पास मुख्य भूमि चीन के अन्य इलाकों के मुकाबले क्रोमियम और क्रूप्रम के ज्यादा बड़े भंडार हैं। तिब्बत में 12 अन्य खनिजों के भंडार भी पूरे देश के पांच शीर्ष भंडारों में से हैं। चीन के एल्युमिनियम और तांबे की विशाल कंपनियों एल्युमिनियम कॉर्प ऑफ चाइना और चाइनाल्को ने यहां अपनी इकाई लगाई है और चीनी खनन कंपनियों जैसे वेस्टर्न माइनिंग कंपनी और जिजिन माइनिंग ग्रुप कंपनी ने दक्षिण–पूर्वी तिब्बत के युलांग तांबा भंडार से उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

चीन ने सेना नियमों में संशोधन कर 'गृह युद्ध' से निपटने पर जोर दिया

(समयलाइव, 8 फरवरी)

चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए नियमों में 'बदलाव' किए हैं ताकि सूचनाओं की कमी के बावजूद स्थानीय लड़ाइयों यानी गृह युद्ध से निपटने की क्षमता बढ़े और युद्ध के दौरान अन्य तरह के सैन्य अभियान चलाने की क्षमता भी बढ़े। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपनी 90वां वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए पार्टी सेना पर अपना 'पूरा' नियंत्रण बनाए रखना चाहती है ताकि सामाजिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। एक शीर्ष चीनी अधिकारी ने हाल में यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि दूसरे देशों की सेनाओं के विपरीत चीन की जनमुक्ति सेना का दर्जा अलग तरह का है क्योंकि यह कम्युनिस्ट पार्टी के सीधे नियंत्रण में काम करती है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व करने वाले चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के मुखिया वहां के राष्ट्रपति हू जिनताओ हैं जो पार्टी के महासचिव भी हैं। हाल में चीन के रक्षा मंत्री जनरल लियांग गुआंगली ने इस बात पर जोर दिया था कि समूचे चीन में गृहयुद्ध जैसी चीज तो संभव नहीं, लेकिन क्षेत्रीय संघर्षों के शुरू होने से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन ने अपने रक्षा खर्चों के लिए पिछले साल 77 अरब डॉलर का बजट आवंटन किया था। हाल में उसने अब तक छुपाए गए लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया है और वह इस साल अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने वाला है जो पुराने यूक्रेन के विमानवाहक का नया संस्करण होगा।

'तिब्बती पहचान को मिटाने के लिए आया है नया चीनी कानून'

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 फरवरी)

अगले माह से प्रभावी होने वाला नया चीनी कानून तिब्बती पहचान और उसकी समृद्ध संस्कृति को मिटाने के लिए बना है। निर्वासित तिब्बती सरकार ने धर्मशाला में एक बयान जारी कर यह बात कही। इस कानून में परमपावन और अन्य बौद्ध भिक्षुओं के तिब्बत में अवतार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे ने कहा कि दलाई लामा और अन्य तिब्बती लामाओं के अवतार पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी करने वाला नया चीनी कानून कोई अचरज की बात नहीं है और इसकी आशंका सबको थी। उन्होंने कहा कि चीन काफी लंबे समय से कई ऐसे तरीके और फॉर्मूला निकालने की कोशिश में लगा हुआ था जिससे तिब्बत की दो प्रमुख धार्मिक संस्थाओं, दलाई लामा और पंचेन लामा को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये दोनों संस्थाएं तिब्बतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि नया चीनी कानून और कुछ नहीं बल्कि तिब्बती धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण की एक चाल है। उन्होंने कहा कि चीन शायद दलाई लामा के निधन का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उनके निधन से तिब्बत मसले का हल हो जाएगा। रिनपोछे ने कहा कि चीन यह मानता है कि अपना दलाई लामा चुनकर जैसा

कि उसने पंचेन लामा के मामले में किया और नए कानून के सहारे वह धर्मशाला सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तिब्बतियों पर नियंत्रण पा लेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन सरकार की यह खुशफहमी है कि यदि दलाई लामा का निधन हो जाता है तो उसके लिए तिब्बतियों के आंदोलन और संघर्ष को अपनी सुविधा के हिसाब से नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तिब्बत मसले ने वैश्विक स्तर पर चीन पर भारी दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि तिब्बती संघर्ष को सिर्फ एक व्यक्ति (दलाई लामा) से जोड़कर नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह एक पूरे देश का संघर्ष है।

साल 2017 तक सिक्किम सीमा तक पहुंचेगी चीनी ट्रेन

(टिबेटनरीव्यू डॉट नेट, 15 फरवरी)

साल 2017 तक चीन न केवल ल्हासा–शिगास्ते रेल मार्ग का निर्माण पूरा कर लेगा, बल्कि इस नेटवर्क को बढ़ाकर वह नेपाल की सीमा के पास स्थित ड्रैम (चीनी में झांगमू) और भारत की सीमा में सिक्किम के पास स्थित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुम्बी घाटी में यादोंग (यातुंग जिसे ड्रोमो भी कहा जाता है) तक ले जाएगा। जनवरी माह में चीन के 'दीर्घकालिक रेलवे नेटवर्क योजना' को दर्शाने वाले चीनी रेलवे के नक्शे से इस बात की पुष्टि होती है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 14 फरवरी को यह खबर दी गई है। इस नक्शे में बताया गया है कि ल्हासा से झांगमू तक रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा जिसके बाद इसे नेपाल के अंदर काठमांडू तक ले जाना संभव होगा। रेलवे की योजना के अनुसार एक और रेल लाइन शिगास्ते से पूरब की ओर बिछाई जाएगी जो चुम्बी घाटी की शुरुआत में यादोंग तक जाएगी। यादोंग कस्बा नाथू ला दर्रे के द्वारा सिक्किम से जुड़ा है और भारत, चीन और भूटान के त्रिकोण पर स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार यादोंग के पास स्थित इलाके पर भूटान और चीन में विवाद चल रहा है और 1962 में इस इलाके में सैन्य संघर्ष भी देखा गया था, भारत ने नाथू ला दर्रे को बचाने का प्रयास किया। चीन ने इसके साथ ही अन्य कई रेल मार्गों की योजनाओं के बारे में बताया है, लेकिन इन्हें अभी कागजी दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है।

चीन ने दलाई लामा से नए सिरे से लड़ने का आह्वान किया

(एपी–बीबीसी, 25 फरवरी)

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष नेता ने आह्वान किया है कि दलाई लामा के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ नए सिरे से लड़ाई लड़ी जाए और तिब्बती बौद्ध धर्म पर नियंत्रण को और सख्त बनाया जाए। चीन की सरकारी मीडिया ने यह खबर दी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में सर्वोच्च क्रम से चौथे पायदान के नेता जिया क्विंगलिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आयी है जब कुछ हफ्तों बाद ही दशकों से जारी चीनी शासन के खिलाफ हुए अब तक के सबसे व्यापक जनक्रांति की तीसरी वर्षगांठ है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार 24 फरवरी को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में जिया ने कहा, "हमें दलाई लामा गुट के खिलाफ लड़ाई तेज कर देनी चाहिए, स्थिरता बनाए रखने का हर काम ज्यादा सतर्कता से करना चाहिए और तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में भी ठोस काम करना चाहिए।" बीबीसी की एक खबर में भी कहा गया है कि इस बैठक में चीन के जनसुरक्षा मंत्री मेंग जियांझू की उपस्थिति से यह पता चलता है कि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण बनाए रखना एक बड़ा मसला है।

नेपाल में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों पर अपनी राष्ट्रीय पहचान को प्रकट करने से बचने का दबाव है क्योंकि उनका मेजबान देश अपने शक्तिशाली उत्तरी पड़ोसी चीन के करीब हो गया है।

तिब्बती गायक को कैद से रिहा किया गया

(रेडियो फ्री एशिया, 8 फरवरी)

लोकप्रिय तिब्बती गायक ताशी धोनडुप को 15 माह की सजा के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। तिब्बत की आज़ादी के आह्वान वाले गीत रिकॉर्ड करने की वजह से ताशी को चीनी प्रशासन ने जेल में डाल दिया था। उन्हें 8 फरवरी को क्विंघई प्रांत की राजधानी जिनिंग स्थित एक चीनी जेल से रिहा किया गया। उनके एक रिश्तेदार ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी। रिहा होने के बाद शाम को जब वह माल्हो प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित अपने गृह नगर युलगन काउंटी पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने स्कॉर्फ और ग्रीटिंग के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। उनका गर्मजोशी से स्वागत करने वालों में उनके परिवार के लोग, प्रशंसक, दोस्त और अन्य रिश्तेदार थे। ताशी को '58' और 'बिना निशान के प्रताड़ना' नामक दो सीडी के निर्माण की वजह से 3 दिसंबर, 2009 को हिरासत में ले लिया गया था और इसके बाद उन्हें 15 महीने के लिए कठोर श्रम के साथ कारावास की सजा सुनाई गई। इसके पहले भी ताशी को 16 अप्रैल और 19 अप्रैल, 2009 को युलगान काउंटी की पुलिस ने गिरफ्तार कर

साल 2005 में उन्होंने गांसू प्रांतीय बौद्ध संस्थान में दाखिला लिया और साल 2009 में वहां से स्नातक किया।

नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए

पूछताछ की थी और उन्हें '58' शीर्षक का गीत न गाने की चेतावनी दी गई थी। इस गीत में 1958–59 के विफल तिब्बती जनक्रांति को याद किया गया था जिसमें दलाई लामा सहित हजारों तिब्बतियों को निर्वासित होकर भारत आने को मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद जब उनके नए सीडी 'बिना निशान के प्रताड़ना' की हजारों कॉपी बाजारों में दिखने लगी तो उन्हें फिर से जिनिंग में हिरासत में ले लिया गया।

स्पष्टवादी तिब्बती लेखक को फिर से गिरफ्तार किया गया

इस क्षेत्र में भारत पर अंकुश रखने के लिए चीन को पाकिस्तान की जरूरत है, ताकि वह हिंद महासागर में अपनी पहुंच रखे और खनिज संसाधनों से भरे देश अफगानिस्तान से अमेरिकी एवं नाटो सैनिकों के हटने के बाद वहां तक भी पहुंच बना पाए।

(टिबेटनरीव्यू डॉट नेट, 6 फरवरी)

तिब्बत के गांसू प्रांत के सांगचू काउंटी में चीनी अधिकारियों ने 16 दिसंबर, 2010 को एक युवा तिब्बती लेखक को गिरफ्तार कर लिया। इस लेखक को पहले भी गिरफ्तार किया गया था और इसे अक्टूबर, 2010 में ही छह माह के परख अवधि के तहत रिहा किया गया था। धर्मशाला के तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने 4 फरवरी को यह जानकारी दी है। केंद्र ने बताया कि इस लेखक का नाम कालसांग सुल्त्रिम है और वह गित्सांग ताकमिग के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें फिर से गिरफ्तार करने की वजह का पता नहीं चल पाया है। उन्हें सोए शहर के पुलिस मुख्यालय बुलाया गया और उसके बाद वह लौट नहीं पाए। कालसांग को इसके पहले 27 जुलाई, 2010 को सिचुआन प्रांत के जोएगे काउंटी से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाले वीसीडी लोगों को बांटे थे जिसमें उन्होंने चीन सरकार के शासन और अधिकृत तिब्बत में उसकी नीतियों की जमकर आलोचना की थी। करीब एक घंटे के इस वीसीडी की रिकॉर्डिंग 18 अगस्त, 2009 को की गई थी और इसे गांसू, क्विंघई और सिचुआन प्रांत के तिब्बती इलाकों में बड़े पैमाने पर बांटा गया था। हालांकि इस वीसीडी को बांटे जाने का उद्देश्य मूलतः अशिक्षित और आम तिब्बती जनता को 'तिब्बती स्वतंत्रता संघर्ष का सही इतिहास, मध्यम मार्ग नीति के द्वारा वास्तविक स्वायत्तता हासिल करने के दलाई लामा के आह्वान और तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति की जानकारी देना' तथा 'नियमित रूप से जारी सरकार प्रायोजित दुष्प्रचार' का जवाब देना बताया गया। यह भी बताया जा रहा है कि इस वीसीडी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यह आग्रह किया गया था कि 'वह तिब्बत में दमन खत्म करने के लिए तत्परता से काम करें' और दलाई लामा से तिब्बत लौटने का भी आह्वान किया गया था। कालसांग अपने लेखन से काफी चर्चित रहे हैं और खासकर साल 2008 में आई उनकी एक किताब बहुत प्रसिद्ध हुई जिसमें तिब्बती जनता की चिंताओं और आकांक्षाओं को दर्शाया गया था। वह इसके पहले गांसू प्रांत के सांगचू काउंटी में स्थित गित्सान गेदेन छोकोरलिंग मठ में भिक्षु थे। साल 2005 में उन्होंने गांसू प्रांतीय बौद्ध संस्थान में दाखिला लिया और साल 2009 में वहां से स्नातक किया।

नेपाल में चीनी दबाव महसूस कर रहे हैं तिब्बती

(रेडियो फ्री एशिया, 9 फरवरी)

कई जानकारों का कहना है कि नेपाल में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों पर अपनी राष्ट्रीय पहचान को प्रकट करने से बचने का दबाव है क्योंकि उनका मेजबान देश अपने शक्तिशाली उत्तरी पड़ोसी चीन के करीब हो गया है। नेपाली राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले और अक्सर वहां का दौरा करने वाले लेखक मिकेल दुनहाम ने कहा, "चीन और नेपाल के बीच संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं, दोनों देशों के बीच हाल में हुए समझौते और बैठकों को तिब्बतियों के लिए बुरी खबर के रूप में ही देखा जा सकता है।" दुनहाम ने बताया कि नवंबर, 2010 में चीन ने नेपाल पुलिस के लिए दो हफ्ते का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ताकि उन्हें नेपाल में 'तिब्बत समर्थक, चीन विरोधी गतिविधियां और प्रदर्शन रोकने में मदद मिले। उन्होंने कहा, "इसके बाद दिसंबर, 2010 में नेपाल और चीन अपने परस्पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने पर राजी हुए। यह निश्चित रूप से तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के लिए नेपाल में आना कठिन बनाने के लिए उठाया गया कदम था। नेपाल में फंसे तिब्बती शरणार्थियों में पहले भी निराशा थी।" उन्होंने कहा, "अब सिर्फ अंतर यह है कि तिब्बती यह बात समझने लगे हैं कि काठमांडू में कोई भी पार्टी सरकार में आए, नेपाल सरकार पूरी तरह चीन समर्थक रहेगी और इसलिए वह तिब्बतियों के अधिकारों के लिए बहुत मामूली सहानुभूति दिखाएगी।" वाशिंगटन के इंटरनेशल कैंपेन फॉर टिबेट (आईसीटी) की अध्यक्ष मैरी बेथ मार्की भी इस बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि "अब वह नेपाल के तिब्बतियों में असुरक्षा की भावना देख रही हैं जो समय–समय पर और बढ़ जाता है।" उन्होंने कहा, "आपको बता दें, वहां किस्सों की कमी नहीं है। नेपाल में रहने वाले तिब्बती आपको बताएंगे कि नए

आने वाले तिब्बतियों में तो बहुत से चीन के जासूस होते हैं।" मार्की ने बताया कि अब तो हाल यह है कि तिब्बतियों के धार्मिक समारोहों और सामुदायिक कार्यक्रमों को भी नेपाली प्रशासन के अधिकारी संदेह की नजरों से देखते हैं। ब्रिटेन के तिब्बत राहत फंड के प्रायोजन समन्वयक सेरिंग पसांग ने कहा कि नेपाली अधिकारियों ने पिछले साल तिब्बतियों को दलाई लामा के जन्म दिन उत्सव मनाने की इजाजत दे दी थी, इसके बावजूद इस कार्यक्रम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। पसांग ने बताया, "यह कार्यक्रम काठमांडू के बाहर जवालाखेल तिब्बती बस्ती में आयोजित किया गया था, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने मुख्य प्रवेश द्वार का घेराव कर लिया और बौद्धनाथ या स्वयंभूनाथ की तरफ से इस कार्यक्रम में भाग लेने आने वाले तिब्बतियों को गिरफ्तार कर लिया गया।" इस प्रकार केवल बस्ती के भीतर रहने वाले तिब्बती और पुलिस को चकमा देकर वहां पहुंचने वाले लोग ही इस उत्सव में शामिल हो सके। पसांग ने कहा कि नेपाल में कार्यरत तिब्बती कल्याण सोसाइटियां अब बड़े जमावड़े वाले कार्यक्रम या बैठकें करने से बच रही हैं क्योंकि नेपाल में अब यह सब जान चुके हैं कि तिब्बती शरणार्थी समुदाय को समय–समय पर अघोषित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और यह अधिकारियों की मनमानी पर निर्भर होता है।

चीन को राजनीतिक उदारीकरण की जरूरतः दलाई लामा

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 फरवरी)

चीन को बिना साम्यवादी विचारधारा वाला साम्यवादी देश बताते हुए दलाई लामा ने कहा कि चीन में तत्काल राजनीतिक उदारीकरण की जरूरत है। तिब्बत की स्वायत्तता के लिए अपनी मांग को फिर से दोहराते हुए उन्होंने तिब्बती संस्कृति, मूल्यों, जीवनशैली, भाषा, परंपरा और रीति–रिवाजों के चीन द्वारा तेजी से दमन और तिब्बत में चीनी संस्कृति थोपने पर चिंता जताई। अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा 'नालंदा विचारः प्राचीन भारत की निधि' विषय पर आयोजित एक व्याख्यान में उन्होंने यह बात कही। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को मानवता के हित में उस शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहिए। उन्होंने तिब्बतियों को भारत का शिष्य बताते हुए कहा कि तिब्बती परंपरा नालंदा शिक्षा प्रणाली की सच्ची विरासत है। उन्होंने कहा, "हमें इस प्रणाली को बनाए रखने का गर्व है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा गुरू भारत नालंदा परंपरा को संरक्षित नहीं रख पाया जो प्रयोगों, तर्क और अन्वेषण पर आधारित सच्ची बहुलवादी व्यवस्था थी, न कि सिर्फ उद्धरणों पर आधारित। मौजूदा शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें नैतिक मूल्यों की कमी है। उन्होंने कहा, "लेकिन अब कई देशों में शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष सहिष्णुता पर आधारित नैतिक मूल्यों के प्रेरक बनाने के लिए चिंता बढ़ रही है।"

चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है।

चीन परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ कर रहा है हमले

(यूरेशिया रीव्यू, 2 फरवरी)

अशोक के. मेहता

अपने साझे दुश्मन भारत के खिलाफ चीन–पाकिस्तान का सदाबहार रणीनीतिक गठबंधन कम से कम 50 साल पुराना है और इसका दोनों को फायदा हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु और मिसाइल जैसे परंपरागत हथियार देकर पाला–पोसा है और उसे अमेरिकी प्रभाव से दूर रखने की कोशिश में अंतरराष्ट्रीय समर्थन एवं राजनयिक समर्थन मुहैया कराया है। जब 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा तब भी चीन ने उसका समर्थन किया और वह हमारे उत्तर–पूर्वी सीमा पर अलगाववादियों को भी समर्थन देता रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब जमात–उद–दावा को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का प्रयास हो रहा था चीन ने इसे रोक दिया। इस क्षेत्र में भारत पर अंकुश रखने के लिए चीन को पाकिस्तान की जरूरत है, ताकि वह हिंद महासागर में अपनी पहुंच रखे और खनिज संसाधनों से भरे देश अफगानिस्तान से अमेरिकी एवं नाटो सैनिकों के हटने के बाद वहां तक भी पहुंच बना पाए। चीन अपने सीक्यांग प्रांत से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से एकीकृत करना चाहता है और पाकिस्तान की मदद से उइगर आंदोलन पर अंकुश रखना चाहता है। चीन ने यह भी नहीं स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार और मिसाइल हैं। जम्मू–कश्मीर मसले से चीन का जुड़ाव व्यापक रूप से चीन–भारत प्रतिद्वंद्विता का ही हिस्सा है, लेकिन यह चीन की उस बड़ी रणनीति का ही एक अंग है जिसके तहत वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के माध्यम से हिंद महासागर के गर्म

सेना ने यहां स्थानीय, उच्च अक्षांशों पर लड़ने में प्रशिक्षित जवानों की बटालियन तैयार की है, 14 हवाई पट्टियों को उन्नत बनाया है और सड़कों का आधुनिकीकरण किया है।

विवादित गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्र में उपस्थित चीनी सेना की बढ़ती संख्या और वहां की 14 परियोजनाओं में 6 अरब डॉलर से ज्यादा के चीनी निवेश से यह समझा जा सकता है कि कश्मीरमसले और भारतीय कश्मीर तथा वहां के लोगों के बारे में चीन की नीति में पूरी तरह से बदलाव क्यों आ गया है।

जल तक पहुंच बनाना चाहता है। खुनजरब–ग्वादर सामरिक कॉरीडोर का बहुत व्यापक इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन के पास जम्मू–कश्मीर का 43,180 किलोमीटर हिस्सा है। इसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने 1949 के कराची समझौते और 1950 के यूनसीआईपी का उल्लंघन करते हुए चीन को अर्पित कर दिया था और चीन ने 1950 के दशक में लद्दाख में 37,350 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली थी जिसके माध्यम से उसने अक्साई चिन होते हुए तिब्बत तक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी–पश्चिमी संपर्क तैयार किया है। जम्मू–कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्र का 45 फीसदी हिस्सा भारत के पास, 35 फीसदी पाकिस्तान के पास और 25 फीसदी हिस्सा चीन के पास है। चीन द्वारा अक्साई चिन हड़पने और पाकिस्तान द्वारा उसे शक्सगम घाटी उपहार में मिलने के बाद चीन ने जम्मू–कश्मीर पर बोलना शुरू कर दिया। चीन अपने आर्थिक चमत्कार और सेना के बेहतरीन आधुनिकीकरण की वजह से शांत रहने की नीति अपनाए हुए था, लेकिन 2008 के बाद उसने यह नीति छोड़ दी और उसके शब्दों एवं इरादों में बदलाव देखा जाने लगा। भारत की अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी और उसकी पूर्व की ओर देखो नीति जिसे चीन अपने घेराव का तरीका मानता है, चीन के एशिया में प्रभुत्व बनाने के रास्ते में विरोध के नए कारक हैं।

भारत–चीन सीमा वार्ता के लिए चीन बुनियादी शर्तें बदलना चाहता है। जम्मू–कश्मीर की 1,500 किलोमीटर सीमा काटकर और उसे 3,488 किलोमीटर से घटाकर 2,000 किलोमीटर करके वह भारत के इस दावे को भी चुनौती दे रहा है कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। अब वह पूर्वी क्षेत्र में 'जनसंख्या वाले इलाकों में परेशानी न खड़ा करने' के तयशुदा राजनीतिक सोच पर भी अपने पत्ते दबा चुका है। जम्मू–कश्मीर के लोगों के लिए नत्थी वीजा की शुरुआत, अधिकृत कश्मीर के लिए ऐसा न करने, उत्तरी क्षेत्र के आर्मी कमांडर को वीजा देने से इनकार करने, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक व्यवहार करने और गिलगित–बाल्टिस्तान में चीनी इंजीनियरों की नियुक्ति करके चीन अपनी तटस्थता खत्म कर अपना पलड़ा भारी कर रहा है और जम्मू–कश्मीर पर भारत की प्रभुता को चुनौती देकर एक द्विपक्षीय विवाद को 'त्रिपक्षीय' बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी सोच यह है कि सीमा विवाद के हल को तब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि चीन इतना मजबूत नहीं हो जाता कि वह निपटारे की शर्तों को अपने आदेश पर तय करवा सके। पिछले तीन दशकों से यह चलन बन गया है कि भारत जहां बार–बार इस मसले को 'तत्काल हल करने' की जरूरत पर जोर देता रहा है वहीं चीन धैर्य बनाए रखने की वकालत करता है और इतिहास का हवाला देता है। चीनी राष्ट्रपति वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछले पांच साल में वह चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ और वहां के प्रधानमंत्री से करीब 20 बार मिल चुके हैं, लेकिन इसका नतीजा बहुत कम निकला है। इसके पहले उन्होंने यह बात गौर की थी कि चीन दक्षिण एशिया में जानबूझकर अपने पांव रख रहा है। हाल में चीनी जासूस की गिरफ्तारी उत्तर–पूर्व के अलगाववादियों और माओवादियों के साथ चीन के फिर से बने रिश्तों के खुलासे से चीन सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। वेन जियाबाओ यह कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति सिर्फ 0.1 फीसदी समय के लिए आई है, लेकिन बाकी 99.9 फीसदी समय में भारत किसी और तरीकों से चीन के हमले का सामना कर रहा है।

भारत ने चीनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाया

(फाइनेंशियल टाइम्स, 1 फरवरी)

भारत ने अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1 फरवरी को वार्षिक आंतरिक सुरक्षा पर संबोधन दिया जिसमें उन्होंने उत्तर–पूर्व में स्थिरता बनाए रखने की अपने प्रशासन की सफलता को रेखांकित किया। कश्मीर में हिंसा बढ़ने और माओवादी आतंकवाद के व्यापक रूप से फैलने जैसी आंतरिक टकराव की स्थिति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में सिंह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे नाजुक इलाके में हुई प्रगति इस साल की 'विशेष उपलब्धि' रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर–पूर्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश को पर्याप्त धन दिया गया है, खासकर सीमा क्षेत्र के विकास और सीमांत इलाको में पोर्टर, खच्चरों के लिए रास्ते बनाने और प्रशासनिक केंद्रों के विकास के लिए। यह क्षेत्र काफी समय से आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास से अछूता रहा है, लेकिन अब यहां सेना भी अपने ज्यादा संसाधन झोंक रही है। सेना ने यहां स्थानीय, उच्च अक्षांशों पर लड़ने में प्रशिक्षित जवानों की बटालियन तैयार की है, 14 हवाई पट्टियों को उन्नत बनाया है और सड़कों का आधुनिकीकरण किया है।

श्री सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने देश भर में अर्द्धसैनिक बलों के 23 नए बटालियन तैयार किए हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा बल में नई भर्तियां भी शामिल हैं और समुद्री तटों की सुरक्षा को भी मजबूत किया गया है। भारत ने यह सब कदम शायद इसलिए उठाया है क्योंकि यहां के सुरक्षा प्रतिष्ठान चीन को इस इलाके में बढ़ते खतरे के रूप में देखते हैं। देर से ही सही, भारतीय अधिकारी अब पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को संदिग्ध नजरों से देख रहे हैं और वे इसे चीन की आक्रामकता मानते हैं।

भारतीय सेना के सियाचीन और लद्दाख डिवीजन में तैनात रह चुके पूर्व कमांडिंग जनरल अनिल लाल ने कहा कि चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने चेताया कि चीन द्वारा तिब्बत में सैन्य परिसंपत्तियों की स्थापना, जनमुक्ति सेना को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने और उसकी लद्दाख जैसे हिमालयी क्षेत्रों में आसानी से पहुंचने की क्षमता से नई दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। मौजूदा समय में सेवारत वरिष्ठ कमांडर जैसे कि वायु सेना प्रमुख पी.वी. नायक का मानना है कि भारत ने अपनी सेना का इतना आधुनिकीकरण कर लिया है कि वह 1962 जैसी हार दोबारा न होने के लिए पर्याप्त है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा है

(इंडियन एक्सप्रेस, 3 फरवरी)

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा और चीनी नक्शे में भारत के इस उत्तर–पूर्वी राज्य को अपना हिस्सा बताने से सचाई बदल नहीं जाएगी। 2 फरवरी को प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) के प्रतिनिधियों तक श्री सिंह ने इस 'सामान्य तथ्य' को पहुंचाया। एएपीएसयू के अध्यक्ष तकाम तातुंग ने यह जानकारी दी। तातुंग के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश हमेशा ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और आगे भी बना रहेगा।" अरुणाचल के निवासियों को नत्थी वीजा देने के मसले पर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इस समस्या को जल्दी सुलझाने के लिए अपना गंभीर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल अलग–थलग नहीं रह सकता और देश के शेष हिस्से की तरह यहां भी विकास का फल पहुंचना चाहिए। तातुंग के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, "साल 2008 में मेरी अरुणाचल यात्रा के दौरान इस बात को रेखांकित किया गया था कि राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए और केंद्र एवं राज्य सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रही है।"

चीन ने अपने नागरिकों को छोड़ने के लिए भारत पर दबाव बनाया

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 5 फरवरी)

चीन ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वह जासूसी के आरोप में पकड़े गए तीन चीनी घुसपैठियों लुई यांग, छेन रैंग और ली जुई दांग को रिहा कर दे। इन तीनों चीनी नागरिकों को 17 जनवरी को भारत–नेपाल सीमा के रुपइडिहा चौकी पर पकड़ा गया था। चीन का विदेश मंत्रालय अपने इन नागरिकों के बचाव के लिए नियमित रूप से बयान जारी कर रहा है और अब चीनी राजदूत झांग यांग ने भी इसके लिए प्रयास शुरू किए हैं। भारत–नेपाल सीमा पर तैनात खुफिया एजेंसियों के लोगों का कहना है कि यांग ने इन लोगों की रिहाई के लिए विदेश सचिव निरुपमा राव के साथ एक लंबी बैठक की है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने चीनी राजदूत से कहा है कि इस देश का कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और पूरी पारदर्शिता से काम करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है ताकि चीनी घुसपैठियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सके।

अब चीनी राजदूत झांग यांग ने भी इसके लिए प्रयास शुरू किए हैं।भारत–नेपाल सीमा पर तैनात खुफिया एजेंसियों के लोगों का कहना है कि यांग ने इन लोगों की रिहाई के लिए विदेश सचिव निरुपमा राव के साथ एक लंबी बैठक की है।

भारतीय सेना ने उत्तर – पूर्व में दो नए पर्वतीय डिवीजन बनाए

(आईएएनएस, 7 फरवरी)

तिब्बत में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए भारत ने उत्तर–पूर्व में 30,000 जवानों वाले दो नए पर्वतीय डिवीजन बनाए हैं ताकि बचाव के उपाय किए जा सकें और पहाड़ी इलाके में युद्ध क्षमता में बढ़त हो। थल सेना मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "हमने अब पूरी तरह उत्तर–पूर्व में दो नए पर्वतीय डिवीजन खड़े कर लिए हैं। वे पूरी तरह से कार्यरत हैं। जल्दी ही इनका सहयोग करने वाला अमला भी साथ होगा।" इनमे से प्रत्येक डिवीजन को खड़े करने में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आयी है। यह डिवीजन कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के नगालैंड के रंगपहाड़ स्थित 3 कॉर्प्स और असम के

(1)

(2)

(10)

कैमरे की

1. निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर सुश्री डोलमा ग्यारी उत
2. हिमाचल के लाहौल स्पीति और किन्नौर क्षेत्र से भी कर्मापा के बहुत से
3. चीन ने देश में सर्च इंजनों पर मिस्र शब्द को प्रतिबंधित कर दिया है और
4. राजस्थान के जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान परमपावन दलाई चंद्रेश कुमारी (बाएं से दूसरी)।
5. 'तिब्बत में भाषा के अधिकारों को लेकर 30 जनवरी से साइकिल यात्रा शुरू क में। ये दोनों छात्र 10 मार्च, 2011 को धर्मशाला पहुंचेगे।
6. तिब्बत के शिगास्ते प्रांत में अंधाधुंध खनन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ति
7. इंटरनेट पर प्रसारित विरोध प्रदर्शन के संदेश को चीनी अधिकारियों द्वा
8. शंघाई में 20 फरवरी, 2011 को 'जास्मीन क्रांति' विरोध प्रदर्शन में शामिल हो व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फोटोः रायटर्स
9. राजस्थान के जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पर
10. परमपावन के दूत केलसांग ग्यालत्सेन (बाएं से तीसरे), 2 फरवरी, 2011 को कालोन त्रिसूर तेथांग तेनजिन नामग्याल (दाएं से तीसरे), कसुर ताशी वांग के बारे में बताते हुए।

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

आंख से

तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात करते हुए। भारतीय अनुयायी उनके समर्थन में 'एकता प्रदर्शन' में हिस्सा लेने धर्मशाला पहुंचे। वह सरकारी समाचार एजेंसियों द्वारा मिश्र से जुड़ी खबरों को जारी नहीं होने दे रहा। लामा (बीच में), जोधपुर के पूर्व शासक गज सिंह (दाएं से दूसरे) और लोकसभा सांसद

रने वाले टीसीवी सूजा के दो छात्र सेल्हो ग्याल और सेरिंग दोर्जी अपने स्कूल यूनिफॉर्म

ब्बती लोगों को रोकने के लिए लगी चीनी सुरक्षा बलों और दंगा पुलिस की कतारें। रा रोक देने के बाद शंघाई की सड़कों पर दिख रही पुलिस। (फोटोः रायटर्स) ोने के इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रसारित आह्वान के बाद पुलिस ने एक

मपावन दलाई लामा, जोधपुर के पूर्व शासक गज सिंह (बाएं से दूसरे)। ो धर्मशाला के कशग सचिवालय में कालोन ट्रिपा पद के तीन आधिकारिक उम्मीदवारों दी (दाएं से दूसरे) और डॉ. लोबसांग सांगे (दाएं से पहले) को तिब्बत–चीन वार्ता

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

(7)

(6)

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए दलाई लामा ने कहा कि इस प्रकार के अस्थिर देशों से घिरे रहने के बावजूद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानव मूल्यों को बनाए रखा है।

तेजपुर स्थित 4 कॉर्प्स के तहत होंगे। प्रत्येक डिवीजन में 15,000 जवान हैं। इससे भारत के परंपरागत विरोधी चीन की सीमा के सामने स्थित महत्वपूर्ण सामरिक इलाकों में भारतीय सेना रणनीतिक रूप से मजबूत होगी। यह नए पर्वतीय डिवीजन ऐसे समय में बनाए गए हैं जब भारतीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी सचेत होकर 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के उस पार चीनी सैन्य बुनियादी ढांचे में भारी उन्नतीकरण को देख रहे हैं। एलएसी दोनों देशों के बीच की युद्ध विराम के बाद तय रेखा है क्योंकि दोनों देशों की सीमा के सभी सेक्टर जैसे पश्चिमी (लदाख), मध्य (उत्तराखंड, हिमाचल) और पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल) में कोई मापांकित सीमा नहीं है। चीन को ध्यान में रखकर भारतीय सेना कुछ और योजनाएं बना रही है जैसे 'अरुणाचल स्काउट' और 'सिक्किम स्काउट' को खड़ा करना जिसे पिछले साल मंजूरी दी गई थी। भारत ने तेजपुर में एक सुखोई–30 लड़ाकू विमान स्क्वार्डन भी तैयार किया है ताकि हवाई हमले की तैयारी मजबूत रहे। इसके अलावा उत्तर–पूर्व की हवाई पट्टियों और हेलीपैड को उन्नत बनाया जा रहा है। थलसेना ने अपने 35 डिवीजन में से 10 डिवीजन पर्वतीय इलाकों में लगा दिए हैं और उच्च अक्षांश के अभियानों के लिए एक और इन्फैंट्री डिवीजन लगा दिए हैं। भारत अमेरिका से 140 एम777 अत्यंत हल्के होवित्जर तोप खरीदने की प्रक्रिया में है। करीब 64. 70 करोड़ डॉलर का यह सौदा भारतीय सेना के 12,000 करोड़ रुपए की लागत से चलने वाले आर्टिलरी आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है। हेलीकॉप्टर गनशिप और हमलावर हेलीकॉप्टर जैसे हवाई संसाधनों से दोनों डिवीजनों को भौगोलिक बाधाओं से निपटने में आसानी होगी।

'गिलगित – बाल्टिस्तान पर कब्जे की ओर बढ़ रहा है चीन'

(टिबेटनरीव्यू डॉट नेट, 8 फरवरी)

विवादित गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्र में उपस्थित चीनी सेना की बढ़ती संख्या और वहां की 14 परियोजनाओं में 6 अरब डॉलर से ज्यादा के चीनी निवेश से यह समझा जा सकता है कि कश्मीर मसले और भारतीय कश्मीर तथा वहां के लोगों के बारे में चीन की नीति में पूरी तरह से बदलाव क्यों आ गया है। 'चीन की गिलगित–बाल्टिस्तान में बढ़ती उपस्थित और उसके क्षेत्रीय निहितार्थ' विषय पर 5 फरवरी को आयोजित एक सम्मेलन में यह बिंदु उभर कर आया। पीटीआई की एक खबर के अनुसार इस सम्मेलन का आयोजन जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज के दक्षिण एशिया कार्यक्रम द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कहा कि इस इलाके में चीन के नागरिकों और सैनिकों की बढ़ती सक्रियता एक चेतावनी वाली बात है और इससे भारत–चीन रिश्ते के साथ ही इस समूचे इलाके में व्यापक शांति पर असर पड़ेगा। सम्मेलन में शामिल वक्ताओं में पत्रकार और वाशिंगटन के थिंकटैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी (अंतरराष्ट्रीय नीति केंद्र) में कार्यकारी निदेशक सेलिग हैरिसन भी शामिल थे। सेलिग ने पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक लेख में कहा था कि काराकोरम राजमार्ग निर्माण करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गिलगित–बाल्टिस्तान सीमा पर खुनजेराब दर्रे में चीन की जनमुक्ति सेना के कम से कम 7,000 जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा, "यह सीधे–सीधे सत्ता हथियाने की जगह धीरे–धीरे नियंत्रण हासिल करने की प्रक्रिया है।" उन्होंने कहा कि इस इलाके के आर्थिक रूप से पिछड़े होने और सामाजिक रूप से बंटे हुए समाजों की वजह से इसे हथियाना आसान जान पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं लोकतंत्र केंद्र (आईसीपीडी) के कार्यकारी निदेशक मुमताज खान ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के सैनिकों की चेतावनीजनक वृद्धि पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले समूचे विवादित कश्मीर पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गिलगित–बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की मौजूदा भूमिका सिर्फ सैन्य और राजनयिक समर्थन देने से कहीं ज्यादा है। खान का मानना है कि बहुत जल्द ही कश्मीर मसले की बागडोर चीन के हाथ में आ जाएगी क्योंकि चीन ने इस मामले में अपने को एक बड़ा खिलाड़ी बनाने का प्रयास किया है। हैरिटेज फाउंडेशन की लीसा क्यूरटिस ने कहा कि यह मानना अभी काफी जल्दबाजी होगी कि चीन गिलिगित और बाल्टिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा, "चीन शायद इस इलाके में व्यापार बढ़ाकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह के द्वारा मध्यपूर्व के साथ अपने आर्थिक संपर्क बढ़ाना चाहता है।"

चीन द्वारा मुद्रा का मूल्य कम रखने से भारत को नुकसानः आरबीआई

(रायटर्स, 8 फरवरी)

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर धुवुरी सुब्बाराव ने कहा कि चीन द्वारा अपने मुद्रा का मूल्य न बढ़ने देने से भारत को कई तरह से 'नुकसान' हो रहा है। चीन पर अमेरिका इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने मुद्रा के मूल्य को ज्यादा तेजी से बढ़ने दे ताकि घरेलू मांग को बढ़ावा मिल सके और दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम हो। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने इसके पहले दिसंबर माह में कहा था कि चीन के साथ अपने बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारत चिंतित है और हमें उम्मीद है कि चीन ऐसी कोई व्यवस्था बनाएगा जिससे भारतीय कंपनियों को चीन में ज्यादा बाजार पहुंच हासिल हो सके। सितंबर की तिमाही में भारत का कुल व्यापार घाटा 35.4 अरब डॉलर का था, जबकि जून की तिमाही में संशोधित आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा 31.6 अरब डॉलर था। भारत का व्यापार घाटा पिछले साल अगस्त माह में बढ़कर 23 माह के उच्चतम स्तर 13.06 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन नवंबर माह में यह गिरकर आठ माह के सबसे निचले स्तर 8.9 अरब डॉलर पर आ गया क्योंकि अक्टूबर माह से आयात के मुकाबले निर्यात बढ़ना शुरू हो गया।

सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर भारत का हक बनता हैः दलाई लामा

(इकनॉमिक टाइम्स, 9 फरवरी)

दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और वीटो पावर के लिए भारत 'सबसे योग्य' उम्मीदवार है। उन्होने कहा कि चीन 'बिना साम्यवादी विचारधारा वाला एक साम्यवादी देश' है और उन्होंने तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के दमन पर दुख जताते हुए कहा कि तिब्बत में चीनी जीवनशैली को थोपा जाना 'अस्वीकार्य' है।

तिब्बत पर चीन से ज्यादा भारत का दावाः दलाई लामा

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 11 फरवरी)

परमपावन दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत पर चीन से ज्यादा अपना दावा करने के भारत के पास वाजिब वजह है। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों का भारत से ज्यादा जुड़ाव है क्योंकि बौद्ध धर्म की जड़ें भारत में हैं और अब भी भारत में सीमा के समानांतर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक इस धर्म का व्यापक चलन है। अपने जोधपुर दौरे पर तिब्बती समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने तिब्बतियों के संघर्ष में भारत से लगातार सहयोग की मांग की क्योंकि उनके हिसाब से यह भारत के लिए भी एक मसला है। उन्होंने कहा कि तिब्बती भारत के काफी ऋणी हैं क्योंकि इस देश ने भारत को कभी भी निराश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि चीन एक तेजी से विकसित होता हुआ देश है जिसमें तेज आर्थिक वृद्धि हो रही है, लेकिन वहां अब भी आज़ादी और नैतिकता की कमी है। इसके विपरीत नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और आज़ादी के मामले में चीन से भारत आगे है और यह दुनिया का सबसे सफल और स्थिर लोकतंत्र है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए दलाई लामा ने कहा कि इस प्रकार के अस्थिर देशों से घिरे रहने के बावजूद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानव मूल्यों को बनाए रखा है।

अपने देश से निर्वासित तिब्बती हमेशा ही अपने कष्टों के क्षण में नैतिक सहयोग के लिए भारत का मुंह देखता है।

'अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार है चीन'

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 फरवरी)

भारत और चीन के अन्य पड़ोसियों को लुभाने की अमेरिकी कोशिश को 'असहनीय' बताते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक लेख में कहा गया है कि चीन को इन देशों को यह 'साफ संदेश' भेजना चाहिए कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए युद्ध करने को भी तैयार है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र क्यूशी जनरल में छपे लेख में कहा गया है कि चीन को अपने इस बुनियादी सिद्धांत से जुड़े रहना चाहिए कि वह युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन उसे जवाबी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। इस क्षेत्र में उभरते अमेरिकी गठजोड़ का जवाब देने के लिए एक आक्रामक रणनीति का सुझाव देते हुए इस लेख में कहा गया है, "हमें अपने पड़ोसियों को यह साफ संदेश देना चाहिए कि हम युद्ध से नहीं डरते और हम अपने राष्ट्र हित की रक्षा के लिए किसी भी समय युद्ध करने को तैयार हैं।"

इस लेख में कहा गया है, "नए चीन के समूचे इतिहास के दौरान (1949 के बाद) चीन में शांति हमेशा युद्ध से ही हासिल हुई है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा कभी भी सिर्फ वार्ताओं से नहीं बल्कि युद्ध से ही हुई है।" लेख में कहा गया है कि जापान, भारत, वियतनाम,आस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कोरिया जैसे देश चीन विरोधी समूह से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि

हमें परमपावन दलाई लामा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक एवं धार्मिक मसलों पर उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी, "उनकी सेनाएं तैयार हैं, वे किसी भी समय हमला कर सकती हैं। चीन हमारा नंबर एक दुश्मन है। यह अपने देश को बचाने का समय है।"

उनका चीन से युद्ध या हितों का टकराव हो चुका है। इसमें कहा गया है, "विशेष रूप से यह असहनीय है कि किस प्रकार अमेरिका चीन के खिलाफ हमारे पड़ोसी देशों को खुलकर उकसा रहा है। लेकिन हम पूरी तरह अमेरिका पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि मक्खी वहीं बैठती है जहां मीठा होता है। वे हमें इस्तेमाल कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।" लेख में सुझाव दिया गया है कि चीन को अपने आर्थिक ताकत और व्यापार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों पर लगाम लगाने के लिए हथियार के रूप में करना चाहिए। लेख में कहा गया है, "चीन के पड़ोसी देशों को चीन से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जरूरत है, चीन के व्यापार घाटे का बड़ा हिस्सा इन देशों की वजह से होता है। इसलिए चीन के विरोध से उन्हें ज्यादा नुकसान होगा, चीन को नहीं। चीन को इन आर्थिक फायदों और सामरिक ताकत का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। यह युद्ध से बचने का भी सबसे प्रभावी साधन है।" लेख में सुझाव दिया गया है कि अमेरिका के खिलाफ जवाबी रणनीति के रूप में अमेरिकी गठजोड़ में शामिल देशों के खिलाफ कठोर नीति अपनानी चाहिए और लातिन अमेरिका एवं अफ्रीका में अमेरिका विरोधी गुट तैयार करना चाहिए।

लेख में कहा गया है कि अमेरिका और अन्य लोकतंत्रों में मीडिया की आज़ादी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक जनमत युद्ध की शुरुआत करनी चाहिए।

भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के रास्ते में चीन की दीवार

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 फरवरी)

हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी उम्मीदों और आशंकाओं पर ध्यान दें।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार के क्रम में स्थायी सीट हासिल करने के भारत के प्रयास में चीन फिर से पत्थर की दीवार साबित हुआ है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी चर्चा के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मा झाओक्सू ने कहा, "सुधारों के लिए पहले से ही परिणाम तैयार करने या अपरिपक्व योजना के लिए मजबूर करने से न केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की एकता कम होगी, बल्कि इससे आखिरकार सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को नुकसान होगा और किसी के भी हित में नहीं होगा।" बीजिंग के इस बयान से दो दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने न्यूयॉर्क में जी–4 के अपने अन्य देशों–ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस अवसर पर जारी एक संयुक्त घोषणापत्र में चारों देशों में हुए इस समझौते पर फिर से जोर दिया गया कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सीटों के जल्दी ही विस्तार के लिए दबाव बनाने हेतु सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए विभिन्न देशों के बीच संवाद की शुरुआत से ही सदस्य देशों ने इसकी प्रक्रिया से जुड़े कई मसलों पर गहन चर्चा की है और कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, "इन चर्चाओं से यह पता चलता है कि कई मसलों पर सदस्य देशों में अभी भी गहरे मतभेद हैं और अभी कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। बीजिंग का यह मानना था कि कई तरह के विवादों को देखते हुए हमें सुधार प्रक्रिया पर संवाद और परामर्श बढ़ा देना चाहिए। हालांकि चीनी प्रवक्ता अपने शब्दों को लेकर काफी सतर्क दिखे जिससे चीन को ऐसा देश न मान लिया जाए जो सुरक्षा परिषद के पांच देशों के विशेष क्लब में प्रवेश करने के इच्छुक भारत एवं जापान को रोकना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपनी आपत्ति सुधार प्रक्रिया को लेकर जताई और कहा कि चीन ने इस बात का समर्थन किया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ऐसे समाधान की मांग करनी चाहिए और गहन एवं लोकतांत्रिक विचार–विमर्श के द्वारा सभी पक्षों के हितों और चिंताओं को समाहित करते हुए सबसे व्यापक सहमति पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।

तिब्बती भारत के सहयोगी हैं

(22 फरवरी, यूरेशिया रीव्यू)

बी रमन

तिब्बती और उइगर विद्रोहों ने यह दिखा दिया है कि आर्थिक समृद्धि से उनकी आज़ादी की भूख कम नहीं हुई है। जब तक आज़ादी के लिए यह मांग जारी रहेगी, चीनी सीमा क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। भारत को चीन की आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर गहरी नजर रखनी चाहिए और बिना किसी फायदा उठाने की कोशिश के बिना इसका अध्ययन करना चाहिए। एक अस्थिर और असुरक्षित चीन भारत के हित में नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को तिब्बतियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वे हमारे सच्चे सहयोगी हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी इस बात के लिए मदद करनी चाहिए कि वे चीन में बौद्ध धर्म को जिंदा रखें। हमें परमपावन दलाई लामा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक एवं धार्मिक मसलों पर

उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए। अपने देश से निर्वासित तिब्बती हमेशा ही अपने कष्टों के क्षण में नैतिक सहयोग के लिए भारत का मुंह देखता है। हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी उम्मीदों और आशंकाओं पर ध्यान दें। चीन की भौगोलिक सीमा के विखंडन के बिना तिब्बती और परमपावन दलाई लामा कैसे एक गर्वित नागरिक की तरह अपने देश वापस लौट सकें, इस सवाल का हल तलाशने पर हमें हमेशा गौर करना चाहिए। ऐसी खबर है कि मिस्र की क्रांति के चीन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों से चिंतित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अब देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक कार्यालय गठित किया है। नई दिल्ली की संस्था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओरआरएफ) द्वारा दिसंबर की शुरुआत में आयोजित एक सेमिनार में चीन की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर पेश किए गए एक शोध पत्र में मैने इस तथ्य पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि चीन अपनी सशस्त्र सेनाओं से ज्यादा आंतरिक सुरक्षा पर खर्च करता है जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर पार्टी नेतृत्व घबराया हुआ है। हान चीनियों की बसावट वाले तटीय क्षेत्रों में आर्थिक अशांति और तिब्बतियों एवं उइगर की आबादी वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में नस्लीय अशांति पर काबू पाते हुए आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना चीन के लिए एक बड़ी चिंता है। यह उनके हालिया बजट आवंटन से ही साफ हो जाता है। ग्लोबल टाइम्स में पिछले साल 23 अगस्त को छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने आंतरिक सुरक्षा साधनों के लिए 76 अरब डॉलर का बजट आवंटन किया है।

चीन–पाक सैन्य खतरे के बारे में सचेत रहे भारतः मुलायम सिंह यादव

(टिबेटनरीव्यू डॉट नेट, 24 फरवरी)

चीन और पाकिस्तान इस साल दो संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने 22 फरवरी को आरोप लगाया है कि दोनों देश भारत पर हमले की रणनीति बना रहे हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए यादव ने कहा, "चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकते हैं। भारत पर हमले के लिए उन्होंने रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री जब जवाब दें तो इस सदन को इस बात का भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि भारत सुरक्षित है।" उन्होंने चेतावनी दी, "उनकी सेनाएं तैयार हैं, वे किसी भी समय हमला कर सकती हैं। चीन हमारा नंबर एक दुश्मन है। यह अपने देश को बचाने का समय है।" दूसरी तरफ, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने 22 फरवरी को खबर दी है कि पाकिस्तान और चीन अपने कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर इस साल वायु सेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे। पाकिस्तान की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल खालिद शमीम वीन ने हाल में चीन का पांच दिन का दौरा किया था। दोनों देश मार्च में आयोजित कई देशों के नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लेंगे। वीन ने तब कहा था, "चीन और पाकिस्तान की साझेदारी इस क्षेत्र में सुविधा और स्थिरता का स्रोत है।" खबर के अनुसार जुलाई, 2010 में उत्तर–पश्चिमी चीन के निंगक्सिया हुई स्वायत्तशासी क्षेत्र के क्विंगटोंगक्सिया में पाकिस्तान और चीन के बीच आयोजित संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का भी वीन ने नेतृत्व किया था।

"वह भारत में तो काफी दान देते ही हैं, विदेश में भी दान भेजते हैं।"

भारत–चीन वार्ता में सहयोग करने का इच्छुक है अमेरिका

(एएफपी, 3 फरवरी)

पूर्वी एशिया के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री कुर्त कैम्पबेल ने कहा कि अमेरिका अब भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है क्योंकि इस उभरते दक्षिण एशियाई देश ने दक्षिण–पूर्व एशिया और जापान में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ किए हैं।

वाशिंगटन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कैम्पबेल ने कहा, "हम इस बात का भी खुलकर समर्थन करते हैं कि भारत और चीन के बीच संवाद बढ़ना चाहिए और हम इसे बढ़ावा देने के लिए काम करने को तैयार हैं। आखिरकार हमें यह लगता है कि अगले दशक में एशिया–प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण नई घटना होगी।" जब साल 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा चीन के दौरे पर गए थे और दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणापत्र जारी कर कहा था कि अमेरिका और चीन दक्षिण एशिया के मामले में परस्पर सहयोग करेंगे तब भारतीय नीति नियंता कुछ संकोच में पड़ गए थे। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि पिछले महीने जब चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ वाशिंगटन के दौरे पर गए थे तब संयुक्त घोषणापत्र में इस तरह की किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। दुनिया के

दलाई लामा ने कहा कि महात्मा गांधी के अहिंसा और सौहार्द के सिद्धांतों से दुनिया के कई नेता प्रेरित रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लेकिन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से एक शांतिपूर्ण दुनिया सुनिश्चित की जा सकती है।

दो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश 1962 में सीमा पर लड़ाई लड़ चुके हैं और इसके बाद कई बार सीमा एवं राजनीतिक विवाद बने रहे, जिसमें चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन करना और भारत द्वारा दलाई लामा एवं अन्य तिब्बतियों का स्वागत करने जैसा मसला भी रहा है। ओबामा प्रशासन अपने शुरुआती दौर से ही अमेरिका एवं चीन के बीच के जटिल रिश्ते को संभालने का प्रयास करता रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन यह भी कहता है कि वह लोकतांत्रिक भारत के साथ वैश्विक साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दलाई लामा ने खुद को मिले दान को अस्पताल को सौंपा

परमपावन ने कहा, "निश्चित रूप से ऐसा होगा, यह निश्चित रूप से होगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।" उन्होंने इसकी एक वजह बताई: "अब ज्यादा चीनी लोग तिब्बती आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।"

(आईएएनएस, 5 फरवरी)

सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन से पता चला है कि परमपावन दलाई लामा ने खुद को मिले दान में से कम से कम एक करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में एक अस्पताल बनाने के लिए दे दिया है। मंडी के आरटीआई कार्यकर्ता लावन ठाकुर द्वारा हासिल जानकारी के अनुसार दलाई लामा ने पालमपुर के विवेकानंद मेडिकल एवं रिसर्च ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए दान दिया है जो धर्मशाला से 40 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहा है। खुद के योगदान के अलावा दलाई लामा ने अपने देश–विदेश में स्थित समर्थकों से निवेदन किया कि वे इस संस्था को दान दें जिसके बाद ट्रस्ट को 1.5 करोड़ रुपए का और चंदा मिल गया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार हैं। दलाई लामा के निवेदन पर न्यूयॉर्क के चार लोगों ने एक ही दिन में एक करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। इस बारे में शांता कुमार ने कहा, "दलाई लामा के अपने शिष्यों से निवेदन करने के बाद ट्रस्ट को विदेश से कुछ दान मिला है।" निर्वासित तिब्बती सरकार के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव थुबटेन साम्फेल ने कहा, "दलाई लामा ने इस बारे में काफी कुछ किया है। उन्होंने ऐसे विश्वविद्यालयों को खुलकर दान दिया है जहां विश्व शांति, करुणा, अहिंसा का अध्ययन होता है और मानव मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। वह भारत में तो काफी दान देते ही हैं, विदेश में भी दान भेजते हैं।"

दुनिया के शीर्ष 25 राजनीतिक हस्तियों में दलाई लामा भी भाामिल

(वायस ऑफ अमेरिका, 7 फरवरी)

तिब्बती नेता दलाई लामा को टाइम पत्रिका द्वारा अब तक के हर समय के ''दुनिया के शीर्ष 25 राजनीतिक हस्तियों'' में शामिल किया गया है। टाइम ने दलाई लामा के बारे में कहा है, "वे न केवल तिब्बती अधिकारों और तिब्बती बौद्ध धर्म के सदगुणों के बल्कि दुनिया भर के लोगों के कल्याण के लिए अंतरधार्मिक सहिष्णुता और शांति के भी महानतम और सबसे मुखर प्रवक्ता है।" पत्रिका ने कहा है, "दलाई लामा की विनम्रता ने उनको दुनिया के कई देशों के प्रमुखों और धार्मिक नेताओं में प्रिय बनाया है और इससे वह तिब्बत के बारे में जागरूकता और सहयोग को दुनिया भर में फैलाने का अवसर मिला है।" टाइम पत्रिका की इस सूची में महात्मा गांधी, सिकंदर महान, नेल्सन मंडेला और अकबर महान को भी शामिल किया गया है।

दलाई लामा ने भारतीय एनजीओ को 30 लाख रुपए दिए

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 फरवरी)

अजमेर के तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज के दौरे के समय दलाई लामा ने हर क्षण का पूरा आनंद लिया–शांति, सहिष्णुता और समृद्धि पर अपने संदेश देने से लेकर ग्रामीणों के साथ फोटो खिंचाने और दोपहर भोज में परंपरागत मिष्ठान के सेवन तक। उन्होंने कहा, "बेयरफुट कॉलेज की अवधारणा से मैं प्रभावित हूं और मैं लंबे समय से यहां आने के इंतजार में था। यह कॉलेज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जॉर्डन और कई अन्य देशों के लोगों के लिए जिस तरह से काम कर रहा है उसे देखकर मैं उत्साहित हूं। आप सब बदलावों के लिए काम कर रहे हैं।" दलाई लामा ने इस कॉलेज को 20 से 30 लाख रुपए का चंदा भी दिया। इस दौरान भाषण में उनका मुख्य जोर दुनिया भर में अमीरों एवं गरीबों के बीच की खाई को दूर करना था। उन्होंने कहा, "दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हर चीज की बहुतायत है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी बुनियादी जरूरत ही नहीं पूरी होती। यह खाई अमेरिका, भारत और यहां तक की साम्यवादी चीन में भी है। बेयरफुट कॉलेज को ऐसा उदाहरण बताते हुए जहां बिना डिग्री वाले लोगों को भी तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है, उन्होंने कहा, "ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे यह खाई दूर हो, अन्यथा इससे गरीब अपने को हीन और कुंठित महसूस करेंगे जिससे वे ईष्यालु और हिंसक बन सकते हैं। इस खाई को दूर करने के लिए गरीबों में

यह भरोसा बनाना चाहिए कि वे भी कुछ कर सकते हैं और अमीरों को उनकी मदद करनी चाहिए जिस तरह से भी की जा सके।गरीबों को खुद को तकनीक से लैस करना चाहिए। वैश्वीकरण के इस युग में सिर्फ कृषि पर निर्भर रहना घातक हो सकता है।"

गांधी ने दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित किया

(टिबेट डॉट नेट, 19 फरवरी)

दलाई लामा ने कहा कि महात्मा गांधी के अहिंसा और सौहार्द् के सिद्धांतों से दुनिया के कई नेता प्रेरित रहे हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में 'प्राचीन बुद्धिमत्ता, आधुनिक सोच' विषय पर एक भाषण के दौरान परमपावन ने यह बात कही। उन्होंने कहा, "भारत में जन्मे महात्मा गांधी के अहिंसा और सौहार्द् के सिद्धांतों से दुनिया के कई नेता प्रेरित रहे हैं। उनके विचारों को मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे दुनिया भर के नेताओं द्वारा सम्मान और स्वीकार किया गया है। वे भारतीय मूल्यों को समझते हैं।" उन्होंने कहा, "अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता भारत की दो निधियां हैं। अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता में यह देश दूसरों के लिए आदर्श रहा है।" परमपावन ने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द् की तारीफ करते हुए कहा कि यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। परमपावन ने कहा, "इस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता जैसा पवित्र शब्द है जिसमें सभी समुदायों और धर्मों का सम्मान करने की बात की गई है।" उन्होंने कहा, "भलाई के लिए भारत को इन पवित्र विचारों को पूरी दुनिया में फैलानी चाहिए। ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जहां विचारों के प्रसार की शुरुआत की जाए। छात्रों को प्राचीन भारत के नेताओं के इन विचारों से जोड़ने के लिए शिक्षाविदों को सबसे आगे रहना चाहिए।

अपने जीवन काल में तिब्बत मसले के हल का दलाई लामा को है भरोसा

(टिबेटनरीव्यू डॉट नेट, 20 फरवरी)

"एक पार्टी शासन के बावजूद चीन पिछले तीस साल में काफी बदला है और आगे भी बदलता रहेगा जिससे ऐसा लगता है कि तिब्बत मसले का हल मेरे जीवनकाल में ही हो जाएगा।" मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करते हुए 18 फरवरी को दलाई लामा ने यह बात कही। दलाई लामा ने कहा, "चीन में उसी एक पार्टी का शासन है, वही एकदलीय शासन, लेकिन इसकी 30 साल पहले से तुलना करें तो वहां काफी बदलाव दिखता है। ये बदलाव के संकेत हैं, पूरी दुनिया बदल रही है।" यह पूछने पर कि क्या उन्हें लगता है कि तिब्बत का मसला उनके जीवनकाल में ही हल हो जाएगा। परमपावन ने कहा, "निश्चित रूप से ऐसा होगा, यह निश्चित रूप से होगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।" उन्होंने इसकी एक वजह बताईः "अब ज्यादा चीनी लोग तिब्बती आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि बदलाव से दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, इस बात पर गौर करें कि जर्मनी और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्वयुद्ध में जंग हुई थी, लेकिन अब वे एक साथ यूरोपीय संघ में मिलकर काम करे हैं। इस विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों और परा स्नातक विभागों के करीब 400 विद्यार्थियों ने संवाद में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम दो घंटे तक चला और इस दौरान छात्रों ने धर्म, दर्शन और पर्यावरण से जुड़े सवाल किए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उच्च एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश तोपे और विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. राजन वेलुकर भी मौजूद थे। दलाई लामा ने 19 फरवरी को मुंबई के परेल स्थित सेंट जेवियर फुटबॉल ग्राउंड में बौद्ध धर्म पर भी एक प्रवचन दिया। बिहार फाउंडेशन, मुंबई के अनुरोध पर उनका यह कार्यक्रम हुआ। इसके पहले 18 फरवरी को दलाई लामा ने मुंबई में एक न्यूरो साइंस पर आयोजित सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने एकेडेमीसिया यूरेशियाना न्यूरोशिरुगिका के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक और परंपरागत ज्ञान एवं तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और स्वस्थ शरीर एवं मानसिक स्थिति के बीच संबंध के आधार पर मानव भावनाओं पर और अनुसंधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अकेले सिर्फ तकनीक से एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और करुणामय दुनिया की गारंटी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि लेकिन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से एक शांतिपूर्ण दुनिया सुनिश्चित की जा सकती है।

नेपाल में अपने पंजे फैला रहा है चीन

(लॉस एजिलिस टाइम्स, 20 फरवरी)

अपने इतिहास के ज्यादातर समय में नेपाल पर भारत का गहरा प्रभाव रहा है। एक लंबी साझी सीमा, साझा धार्मिक परंपराएं और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत एक साझे इतिहास ने दोनों देशों को जोड़ रखा है। नेपाल के उत्तर में 30,000 फुट ऊंचे हिमालय की चोटियों ने इसका चीन से ज्यादा संपर्क नहीं होने दिया।लेकिन अब उभरता हुआ चीन समीकरण बदल रहा है जिससे

चीन करीब 1.9 अरब डॉलर की लागत से तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तिब्बत-नेपाल सीमा तक रेलमार्ग बना रहा है जिसे अंत में काठमांडू तक ले जाया जाएगा। नेपाल में चीनी व्यापार, आर्थिक सहायता और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं तेजी से फैल रही हैं।

भारत की अधीरता बढ़ रही है। आज नेपाल में चीन का प्रभाव व्यापक तौर पर देखा जा सकता है। चीन करीब 1.9 अरब डॉलर की लागत से तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तिब्बत–नेपाल सीमा तक रेलमार्ग बना रहा है जिसे अंत में काठमांडू तक ले जाया जाएगा। नेपाल में चीनी व्यापार, आर्थिक सहायता और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं तेजी से फैल रही हैं। नेपाली नेताओं का बीजिंग का दौरा लगातार हो रहा है और नेपाली पुलिस के प्रशिक्षण, सीमा पर नियंत्रण, सड़कें बनाने से लेकर कूड़ा ढोने वाले ट्रक तक में चीन का पैसा लग रहा है। काठमांडू में रहने वाले हिमाल दक्षिण एशियाई पत्रिका के संपादक कनक मणि दीक्षित ने कहा, "नया चीन अपनी आर्थिक पराक्रम के साथ ही अपने बाहुबल का भी इस्तेमाल कर रहा है। वह भारत को भी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है।" भारत परंपरागत रूप से नेपाल को अपने और चीन के बीच एक बफर देश के रूप में देखता आया है। चीन से भारत 1962 में एक युद्ध हार चुका है। पिछले महीने भारत में तीन चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए जिन पर अवैध तरीके से भारत में घुसने और सामरिक ठिकानों की तस्वीरें लेने का आरोप है। चीन इस बात का खंडन कर रहा है कि वे नागरिक जासूस हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि नेपाल अब निर्वासित तिब्बतियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है जो वहां करीब 20,000 की संख्या में हैं। मार्च, 2008 में समूचे तिब्बत पठार में फैले विरोध प्रर्दशनों के बाद चीन ने नेपाल की तिब्बत नीति में भारी बदलाव कराए। पिछले हफ्ते अमेरिका के अवर विदेश मंत्री मारिया ओटेरो ने नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों की समस्याओं को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री से चिंता जताई। लंबे समय से नेपाल की राजनीति में भारत के कई महत्वपूर्ण समर्थक रहे हैं। साल 2005 में हुए 12 बिंदुओं वाले समझौते में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसमें माओवादियों द्वारा बंदूक छोड़ने के बाद 12 साल तक चले गृह युद्ध का अंत हुआ था। चीनी धन लगातार नेपाल में आ रहा है और इसके साथ ही उसका प्रभाव और दबाव भी आ रहा है।

नेपाली टाइम्स के प्रकाशक कुंडा दीक्षित ने कहा, "समस्या यह है कि हम ड्रैगन के ठीक अगले दरवाजे पर ही हैं। हम अपने पीछे ड्रैगन की आग को महसूस कर रहे हैं। चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कोई भी पश्चिमी देश इसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि छोटा सा देश नेपाल ऐसा कर सकता है?"

रोमर ने कहा, "दलाई लामा से बातचीत करने के लिए कई महत्वपूर्ण मसले थे। जब चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ पिछले माह अमेरिका के दौरे पर गए थे तो राष्ट्रपति ओबामा ने इस बात को रेखांकित किया था कि तिब्बत में मानवाधिकार अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मसला बना रहेगा।

भारत में अमेरिकी राजदूत दलाई लामा से मिले

(हिंदुस्तान टाइम्स, 24 फरवरी)

भारत में अमेरिकी राजदूत तिमोथी जे. रोमर ने कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा के लिए 24 फरवरी को धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती नेता परमपावन दलाई लामा से बंद कमरे में मुलाकात की। अमेरिकी राजदूत ने तिब्बत मसले पर दलाई लामा के चीन से वार्ता का समर्थन किया जो कि पिछले साल नौवें दौर की वार्ता के बाद ठप पड़ा है। दलाई लामा के आवास पर हुई यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। तिमोथी ने दलाई लामा से अपनी मुलाकात को फलदायक बताया। रोमर ने इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, "मैं यहां इस महान स्थान पर इस अत्यंत सम्मानित एवं पवित्र व्यक्ति और दुनिया के एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक नेता से मिलने आया था। मेरे साथ अमेरिका के कई अन्य उच्चाधिकारी आए थे जो परमपावन के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आए थे।" रोमर ने कहा कि उनकी बातचीत के दौरान दलाई लामा के दूतों और चीन के बीच वार्ता को लेकर भी चर्चा हुई जो पिछले साल नौवें दौर की वार्ता के बाद ठप पड़ा है। रोमर ने कहा, "दलाई लामा से बातचीत करने के लिए कई महत्वपूर्ण मसले थे। जब चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ पिछले माह अमेरिका के दौरे पर गए थे तो राष्ट्रपति ओबामा ने इस बात को रेखांकित किया था कि तिब्बत में मानवाधिकार अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मसला बना रहेगा। राष्ट्रपति ओबामा ने यह भी कहा था कि चीनी राष्ट्रपति अपने अधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ लंबे समय से जारी मसलों पर संवाद जारी रखें।" रोमर ने दलाई लामा की इस बात के लिए तारीफ की कि वे चीन प्रशासित तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में पर्यावरण मसलों पर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कहा, "आप उनके साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर चर्चा किए बिना कुछ मिनटों से ज्यादा बात नहीं कर सकते।" इसके बाद अमेरिकी राजदूत और उनकी पत्नी ने ऊपरी तिब्बती बाल ग्रामीण स्कूल (टीसीवी) का भी दौरा किया जहां उन्होंने शिक्षकों और स्कूली बच्चों से बात की। रोमर ने कहा कि उनके धर्मशाला यात्रा का मुख्य उद्देश्य नए आने वाले तिब्बतियों स्वागत केंद्र का उद्घाटन करना था।